अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में राजस्थान का देश में चौथा स्थान
2.	29वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) 2026 : जयपुर
3.	सरिस्का टाइगर रिज़र्व पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण (राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन)
4.	राजस्थान में 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान'
5.	'65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप' में राजस्थान
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. ICAI द्वारा जयपुर में 'क्षितिज' कार्यक्रम का आयोजन 2. निशानेबाज चिरांश चौमिया 3. राज्य स्तरीय सीनियर कॉल्विन शील्ड टूर्नामेंट
7.	महेश दीक्षित बने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के नए निदेशक
8.	किरथई-II जलविद्युत परियोजना
9.	भारत में पर्यटन-आधारित आर्थिक विकास
10.	सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)
11.	रोबोटिक्स क्रांति
12.	एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली 'नेत्र' (Netra)

राजस्थान परिदृश्य

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में राजस्थान का देश में चौथा स्थान

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान 33 लाख से अधिक MSME इकाइयों के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के मामले में देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है।

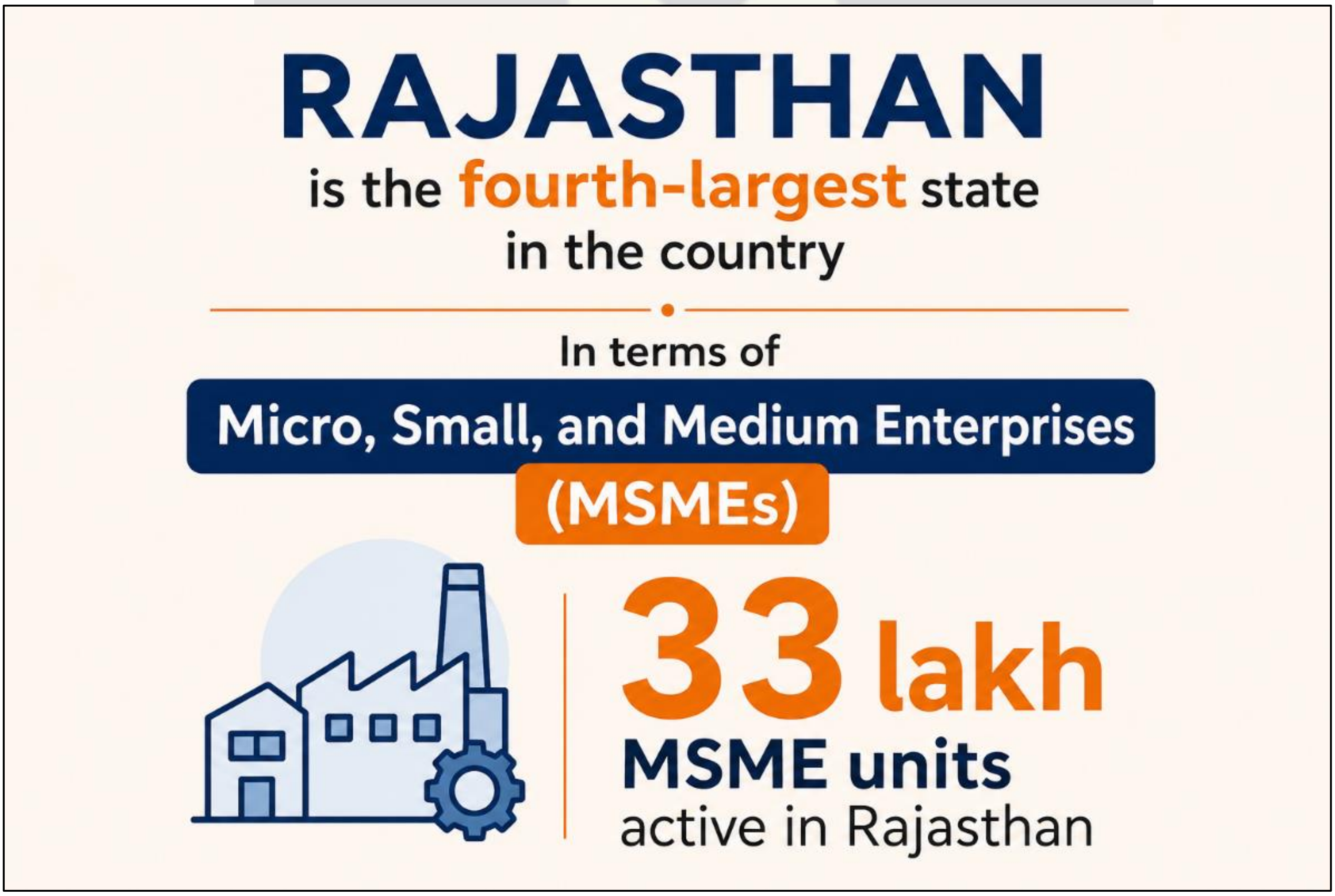

मुख्य बिन्दु:

- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित पहले 'राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस' समारोह के दौरान इसकी जानकारी दी।

अंतरराष्ट्रीय MSMEs दिवस के दौरान अन्य प्रमुख घोषणाएँ:

- **हाटों का विकास :** हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों के लिए PPP (Public-Private Partnership) मॉडल पर हाटों का विकास एवं संचालन। (प्रथम चरण : पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में हाटों का विकास किया जाएगा।)
- **पंच गौरव योजना :** राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'पंच गौरव योजना' में चिन्हित प्रजातियों एवं वनस्पति संबंधी प्रसंस्करण इकाइयों को 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना' (ODOP) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **RIPS – 2024 में संशोधन : राजस्थान** सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) में व्यापक बदलाव करने की घोषणा की गई। जैसे -
  1. नीति में MSMEs के लिए कैपिटल सब्सिडी की अवधि को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष किया गया है।
  2. इलेक्ट्रॉनिक्स & सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत चयनित कंपोनेंट श्रेणियों के लिए RIPS-2024 में न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर ₹15 करोड़ कर दिया गया है।
  3. वर्तमान में RIPS - 2024 के अंतर्गत अधिकतम 3 चरणों में निवेश की अनुमति है। नए प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को 5 चरणों में निवेश की अनुमति होंगी।
- **कौशल एवं प्रशिक्षण के लिए भत्ते में वृद्धि :** इलेक्ट्रॉनिक्स & सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कौशल एवं प्रशिक्षण के लिए महिला एवं दिव्यांग कार्मिकों का अधिकतम भत्ता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रति माह करने की घोषणा।
- **नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता :** राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड (RVCF) के माध्यम से वित्त वर्ष 2026-27 में 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी-2025 :** राजस्थान में MSMEs को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी-2025' लागू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप विगत एक वर्ष में राज्यभर में 1600 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया है। वहीं, 23 प्राथमिक वाले क्षेत्रों में जरूरी सुधार लागू किए हैं।
- साथ ही, राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में MSMEs इकाइयों के लिए 'लैंड यूज अप्रूवल' की समय-सीमा 60 दिनों से घटाकर 30 दिन, उद्योग शुरू करने में दी जाने वाली स्वीकृति जारी करने की समय-सीमा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।
- राज्य सरकार द्वारा गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की 'व्हाइट कैटेगरी सूची' को 104 से बढ़ाकर 877 उद्योगों तक विस्तारित किया गया है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस):

- 27 जून, 2026 को राजस्थान में पहली बार 'अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस' मनाया गया।
- **आयोजन स्थल :** कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर।
- **आयोजक :** उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान।
- **वर्ष 2026 का विषय :** नवाचार और सतत् औद्योगिक विकास के माध्यम से MSME को सशक्त बनाना।
- इस आयोजन के दौरान 'राजस्थान इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट पॉलिसी', 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) कॉफी टेबल बुक' और 'राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस (RAMP) पोर्टल' को लॉन्च किया गया।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:-

Q1. अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस - 2026 के दौरान घोषित प्रथम चरण में किन स्थानों पर 'PPP मॉडल पर हाटों का विकास' किया जाएगा?

(A) जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर

(B) पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर

(C) अजमेर, भरतपुर, सीकर और बूंदी

(D) चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, नागौर और टोंक

Q2. वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से कितने नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई?

(A) 15

(B) 20

(C) 25

(D) 30

CIVIL SERVICES

29वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) 2026 : जयपुर

चर्चा में क्यों?

- जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में 1 और 2 जुलाई, 2026 को 29वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) आयोजित किया जाएगा।

मुख्य बिन्दु:

SERVICES

- **विषयवस्तु :** विकसित भारत 2047 : AI एनेबल्ड, डेटा ड्रिवेन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेन्स' (Viksit Bharat 2047 : AI Enabled, Data-Driven and Secure Digital Governance)
- **आयोजक :** प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से।
- **नॉलेज पार्टनर :** नैस्कॉम एवं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT), जयपुर।

- **पुरस्कार :** केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार तथा 1 जूरी पुरस्कार शामिल हैं।
- **सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित प्रमुख सेशन :** 'एआई बेस्ड गवर्नेन्स फॉर ऑल', 'ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड - वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस इन इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विसेज', 'ड्राइविंग अर्बन— ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी', 'एआई फॉर स्मार्ट पुलिसिंग एंड पब्लिक सेफ्टी', 'सिटिजन सेंट्रीक गवर्नेंस: इन्क्लुसिव गवर्नेंस' और 'डिजिटल इंटरवेंशंस टू एनहांस एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन'।
- **ई-गवर्नेंस :** सरकार अपनी प्रशासनिक सेवाओं और सूचनाओं को आम नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी विभागों तक पहुँचाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ; जैसे - इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करती है, उसे ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहते हैं।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

Q1. जयपुर में आयोजित '29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन – 2026' की विषयवस्तु क्या है?

A. डिजिटल इंडिया : सुरक्षित और समावेशी भारत।

B. विकसित भारत 2047 : AI एनेबल्ड, डेटा ड्रिवेन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेन्स।

C. स्मार्ट इंडिया : टेक्नोलॉजी फॉर ऑल।

D. ई-गवर्नेंस फॉर अर्बन डवलपमेंट।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

सरिस्का टाइगर रिज़र्व पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण (राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन)

चर्चा में क्यों?

- अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिज़र्व में बाघों के पुनर्प्रवेश (Reintroduction) के 18 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 28 जून, 2026 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **आयोजक :** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजस्थान वन विभाग के सहयोग से।
- **विषय :** 'बाघ पुनर्स्थापना: अवसर एवं चुनौतियाँ'।
- **विमोचन :** तीन प्रकाशनों; यथा 'भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन हेतु रोडमैप', 'भारत में बाघ पुनर्स्थापना एवं पुर्नबहाली' पुस्तिका तथा 'प्रोजेक्ट चीता वार्षिक प्रतिवेदन' का विमोचन।

- सरिस्का टाइगर रिज़र्व में वर्ष 2005 तक अवैध शिकार के कारण बाघ पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। 28 जून, 2008 को रणथंभौर से बाघों को एयरलिफ्ट करके सरिस्का लाया गया, जो विश्व का पहला सफल बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट था।
- **सरिस्का टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या :** 56 (आँकड़े 28 जून, 2026 तक)

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान में स्थित टाइगर रिज़र्व :-

क्रमांक	टाइगर रिज़र्व	घोषणा का वर्ष	शामिल जिले
1.	रणथंभौर टाइगर रिज़र्व	1973	सवाई माधोपुर, करौली, बूँदी, टोंक
2.	सरिस्का टाइगर रिज़र्व	1978	अलवर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़
3.	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व	2013	कोटा, बूँदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़
4.	रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व	2022	बूँदी, कोटा
5.	धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व	2023	धौलपुर, करौली

Q 1. सरिस्का टाइगर रिज़र्व में बाघों के पुनर्प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2005 तक अवैध शिकार के कारण सरिस्का में बाघ पूरी तरह समाप्त हो चुके थे।
2. 28 जून, 2008 को रणथंभौर से बाघों को एयरलिफ्ट करके सरिस्का लाया गया।
3. यह विश्व का पहला सफल बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट माना गया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

राजस्थान में 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान'

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान' का राज्यव्यापी चरण 28 जून से 30 जून, 2026 तक संचालित किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **अभियान का शुभारंभ :** 28 जून, 2026 को जयपुर से मुख्यमंत्री द्वारा।

- मुख्यमंत्री द्वारा पल्स पोलियो अभियान के पोस्टर 'दो बूँद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार' का विमोचन किया गया।
- **अभियान का संचालन :** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
- **लक्ष्य :** राजस्थान में इस अभियान के तहत लगभग 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए प्रदेशभर में 59,217 बूथ बनाए गए हैं।
- ज्ञातव्य है कि भारत में वर्ष 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की गई। जनवरी, 2011 के पश्चात गत 15 वर्षों में भारत में कोई भी पोलियो का नया केस नहीं पाया गया है।
- 27 मार्च, 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. राजस्थान में 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान' का राज्यव्यापी चरण कब संचालित किया गया?

A. 27 मार्च से 29 मार्च, 2026

B. 28 जून से 30 जून, 2026

C. 1 जुलाई से 3 जुलाई, 2026

D. 15 जनवरी से 17 जनवरी, 2026

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

‘65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप’ में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, ओडिशा में आयोजित ‘65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप’ में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 01 रजत और 03 कांस्य पदक जीते।

मुख्य बिन्दु:

- **रजत पदक :** पुरुष जैवलिन थ्रो में यशवीर सिंह ने 83.72 मीटर के थ्रो के साथ।
- **कांस्य पदक :** महिला जैवलिन थ्रो में उमा चौधरी ने 53.06 मीटर के थ्रो के साथ।
- **कांस्य पदक :** ट्रैक स्पर्धाओं में राहुल बालोदा ने पुरुष 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 40.07 सेकंड में पूरी कर।

- **कांस्य पदक :** महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज में कुमारी पारू ने 10 मिनट 52.28 सेकंड के समय के साथ।
- **प्रतियोगिता का आयोजन :** भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में।
- **आयोजन अवधि :** 24 से 28 जून, 2026 तक।
- इस प्रतियोगिता में राजस्थान के कुल 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते?

A. 01 स्वर्ण और 03 कांस्य

B. 01 रजत और 03 कांस्य

C. 02 रजत और 02 कांस्य

D. 04 कांस्य

Q2. 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. यशवीर सिंह — पुरुष जैवलिन थ्रो — रजत पदक
2. उमा चौधरी — महिला जैवलिन थ्रो — कांस्य पदक
3. राहुल बालोदा — पुरुष 1500 मीटर दौड़ — कांस्य पदक

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

✂️ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**ICAI द्वारा जयपुर में 'क्षितिज' कार्यक्रम का आयोजन** ▪ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जयपुर में CA छात्रों के लिए 'क्षितिज' राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ▪ **स्थल और अवधि :** 27 और 28 जून, 2026 को जयपुर के बिड़ला सभागार में। ▪ **थीम :** "क्षितिज - भारत 2047 के लिए प्रेरणादायक उत्कृष्टता" (Inspiring Excellence for India 2047)
2.	**निशानेबाज चिरांश चौमिया** ▪ जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित '24वीं राजस्थान राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप – 2026' में युवा डेफ (मूक-बधिर) निशानेबाज चिरांश चौमिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते।
3.	**राज्य स्तरीय सीनियर कॉल्विन शील्ड टूर्नामेंट** ▪ **पुरुष वर्ग विजेता :** सीकर। **उप-विजेता :** उदयपुर। ▪ **महिला वर्ग विजेता :** सीकर। **उप-विजेता :** जयपुर। ▪ **फाइनल का आयोजन :** राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) द्वारा सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर में।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राष्ट्रीय परिदृश्य

महेश दीक्षित बने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के नए निदेशक

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का निदेशक नियुक्त करने को दो वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की है। वे तपन कुमार डेका का स्थान लेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- महेश दीक्षित 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हैं तथा आंध्र प्रदेश कैडर से संबंधित हैं।
- यद्यपि उनकी सेवानिवृत्ति अगस्त 2027 में निर्धारित थी, किंतु उन्हें मौलिक नियम (FR) 56(d) तथा अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1A) के अंतर्गत सेवा-विस्तार प्रदान किया गया है।
- इन प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार जनहित में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), कैबिनेट सचिव, गृह सचिव आदि के प्रमुखों की सेवाएँ 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी बढ़ा सकती है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भूगोल एवं भू-विज्ञान

किरथई-II जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों?

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने 820 मेगावाट क्षमता वाली किरथई-II जलविद्युत परियोजना हेतु वन भूमि के सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा की है।

मुख्य बिन्दु:

- किरथई-II जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजना है।
- परियोजना के अंतर्गत 121 मीटर ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बाँध निर्मित किया जाएगा।
- सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद स्वीकृति प्राप्त करने वाली चिनाब नदी की यह तीसरी जलविद्युत परियोजना है।
- इस परियोजना का क्रियान्वयन चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) तथा जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JKSPDC) का संयुक्त उपक्रम है।
- किरथई-I परियोजना, किरथई-II के ऊपरी प्रवाह में स्थित है, जबकि किरू जलविद्युत परियोजना इसके निचले प्रवाह में स्थित है।
- चिनाब नदी पर प्रस्तावित अन्य प्रमुख जलविद्युत परियोजना—
  - सावलकोट
  - दुलहस्ती-II
  - रतले
  - पाकल दुल
  - क्वार
  - किरू
  - किरथई स्टेज-I

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

आर्थिक घटनाक्रम

भारत में पर्यटन-आधारित आर्थिक विकास

चर्चा में क्यों?

- पर्यटन भारत के आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख प्रेरक कारकों में से एक रहा है।

मुख्य बिन्दु:

वर्तमान स्थिति

- विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (WTTC) के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान लगभग 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर है तथा भारत विश्व की अग्रणी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
- वर्ष 2014-2025 के दौरान भारत में 181.25 मिलियन अंतरराष्ट्रीय आगमन तथा 93.35 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन दर्ज किए गए।
- वर्ष 2024 में भारत में 20.6 मिलियन अंतरराष्ट्रीय आगमन दर्ज हुए, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक पर्यटन रैंकिंग में भारत वर्ष 2016 के 25वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2024 में 20वें स्थान पर पहुँच गया।

पर्यटन का महत्त्व

- **आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन:**

- **उदाहरण:** गोवा में पर्यटन होटल, टैक्सी एवं रेस्तरां उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय हस्तशिल्पियों की आजीविका का भी प्रमुख स्रोत है।
- **क्षेत्रीय विकास:** पर्यटन संतुलित क्षेत्रीय विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है।

संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण:

- **उदाहरण:** खजुराहो मंदिर एवं हम्पी में पर्यटन ने इन विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा दिया है।

सॉफ्ट पावर का निर्माण:

- **उदाहरण:** भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं का प्रभावी प्रदर्शन किया गया।

सामुदायिक सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास:

- **उदाहरण:** सिक्किम एवं केरल में होमस्टे पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए आय एवं रोजगार का महत्त्वपूर्ण स्रोत बना है।

सतत् पर्यटन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण:

- **उदाहरण:** केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में इको-टूरिज्म गतिविधियाँ क्षेत्र के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को रोजगार भी प्रदान करती हैं।
- मामल्लापुरम दक्षिण एशिया का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है, जिसे ग्रीन डेस्टिनेशंस सिल्वर सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है।

प्रमुख पहलें

- **स्वदेश दर्शन योजना, 2014:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में एकीकृत एवं विषय-आधारित पर्यटन परिपथों का विकास करना ह
- **स्वदेश दर्शन 1.0:** 15 विभिन्न विषयगत पर्यटन परिपथों के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ से अधिक लागत वाली 76 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

- **स्वदेश दर्शन 2.0 (2022):** इसका उद्देश्य सतत् एवं अनुभव-आधारित पर्यटन का विकास करना है।
- **तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (PRASHAD) योजना एवं आध्यात्मिक पर्यटन:** इस योजना का उद्देश्य देशभर के प्रमुख तीर्थस्थलों पर आधारभूत अवसंरचना का विकास करना है।
- **राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता (SASCI) योजना:** इसका क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- **सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण योजना:** वर्ष 2025 तक 4.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना तथा 10,000 पर्यटन गाइडों के कौशल उन्नयन का प्रस्ताव रखा गया है।
- **प्रौद्योगिकी, संपर्क एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** भारत ने ई-टूरिस्ट वीज़ा सुविधा के विस्तार, NIDHI एवं NIDHI Plus जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों तथा अतुल्य भारत अभियान के माध्यम से डिजिटल प्रचार-प्रसार द्वारा पर्यटन को अधिक सुगम बनाया है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों, उड़ान (UDAN) योजना, हवाई अड्डों के उन्नयन तथा अंतिम मील संपर्क में सुधार के माध्यम से पर्यटन संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।
- **सतत् पर्यटन संबंधी पहलें:** ट्रेवल फॉर लाइफ (Travel for LiFE) पहल के माध्यम से पर्यटकों एवं पर्यटन उद्योग में पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)

चर्चा में क्यों?

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जुलाई 2026 में सेवा उत्पादन सूचकांक प्रारंभ करने जा रहा है।

मुख्य बिन्दु:

सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)

- सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा विकसित एक मासिक उच्च-आवृत्ति संकेतक है, जिसका उद्देश्य भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तनों का आकलन करना है।
- इसे सेवा क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के पूरक के रूप में विकसित किया गया है।
- इसका विकास तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) द्वारा किया गया है, जिसकी अध्यक्षता देबजानी घोष ने की है।

सूचकांक की आवश्यकता

- भारत का सेवा क्षेत्र सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 50% से अधिक योगदान देता है, किंतु अब तक इसके वास्तविक विकास की निगरानी हेतु कोई मासिक संकेतक उपलब्ध नहीं था।
- ISP आर्थिक निगरानी, नीति निर्माण तथा आर्थिक पूर्वानुमान के लिए समयबद्ध एवं विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराएगा।

ISP की प्रमुख विशेषताएँ

- **कवरेज:** यह केवल औपचारिक सेवा क्षेत्र को कवर करता है।
- इसमें अनौपचारिक क्षेत्र तथा गैर-बाजार आधारित सरकारी सेवाएँ सम्मिलित नहीं हैं।
- **आधार वर्ष:** 2024-25

- **कार्यप्रणाली:** इसमें सकल मूल्य वर्धन (GVA) आधारित भारों के साथ स्थिर-भार लासपेयर आयतन सूचकांक का उपयोग किया गया है।
- **वास्तविक विकास का मापन:** यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एवं थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जैसे मूल्य अपस्फीतिकारकों की सहायता से नाममात्र सेवा उत्पादन को वास्तविक उत्पादन में परिवर्तित करता है।

UTKARSH CIVIL SERVICES

विज्ञान प्रौद्योगिकी

रोबोटिक्स क्रांति

चर्चा में क्यों?

- उन्नत रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित "सन्निहित बुद्धिमत्ता" का उदय भारत की पारंपरिक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को मूलभूत रूप से परिवर्तित कर सकता है।

मुख्य बिन्दु:

भारत की पारंपरिक बढ़त

- कई दशकों से भारत को कम लागत वाले प्रचुर श्रमबल की उपलब्धता का लाभ प्राप्त होता रहा है।
- अनेक उद्योगों ने भारत को इसलिए उत्पादन केंद्र के रूप में चुना क्योंकि यहाँ श्रम लागत विकसित देशों की तुलना में कम थी।
- किंतु यदि उद्योगों एवं कारखानों में मानव श्रमिकों के स्थान पर रोबोटों का उपयोग बढ़ता है, तो कम श्रम लागत पर आधारित भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का महत्त्व कम हो जाएगा।

रोबोटिक्स क्या है?

- रोबोटिक्स वह प्रौद्योगिकी है, जिसके अंतर्गत रोबोटों के डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं उपयोग का अध्ययन एवं विकास किया जाता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा मशीन लर्निंग में हुई प्रगति के परिणामस्वरूप ऐसे उन्नत रोबोट विकसित हुए हैं, जो दृश्य पहचान , वाक् पहचान तथा निर्णय-निर्माण जैसे कार्य कर सकते हैं, जिन्हें पहले केवल मनुष्यों की क्षमता माना जाता था।

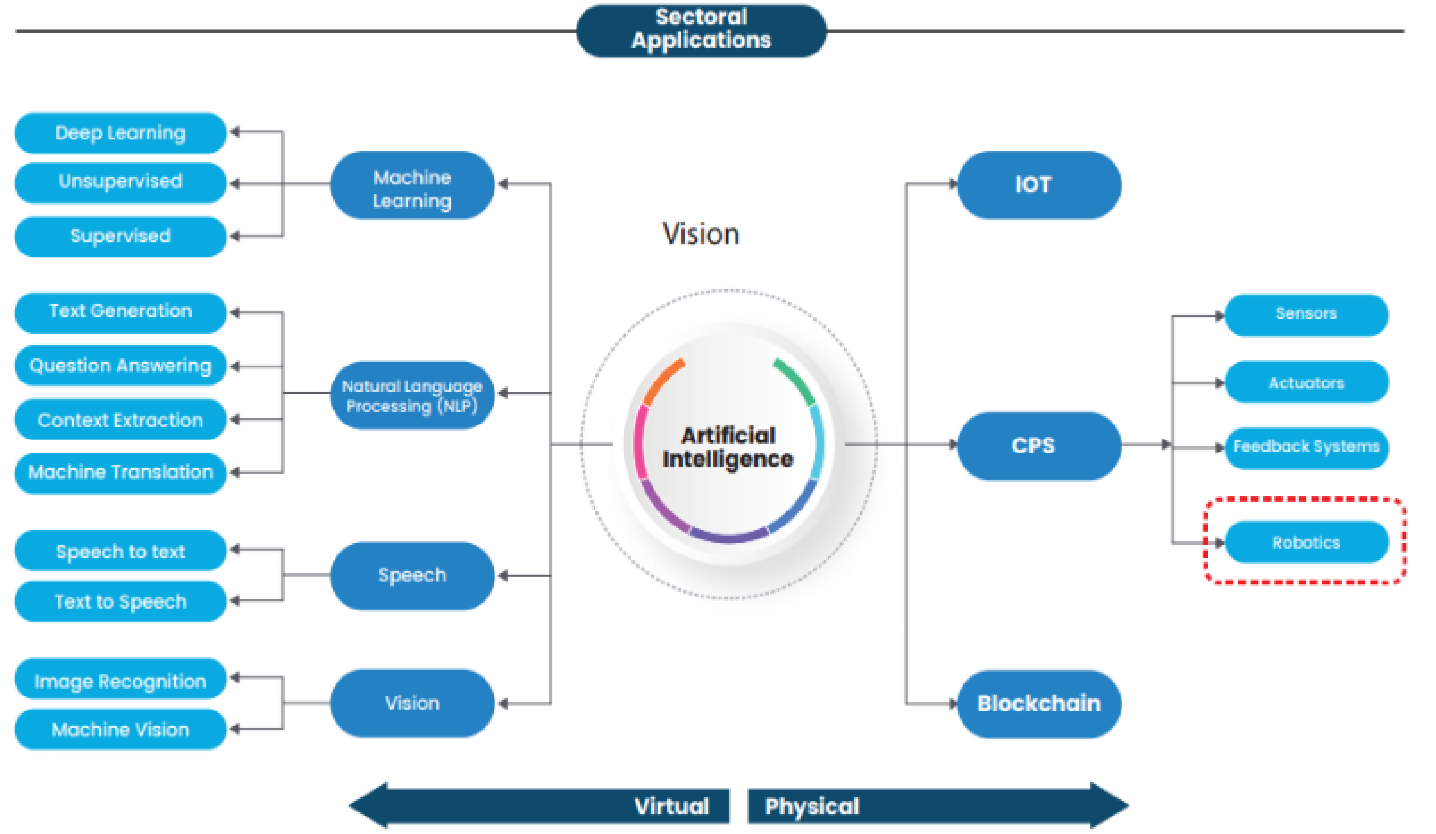

Figure 1: Convergence of AI and Robotics

वैश्विक रोबोटिक्स परिदृश्य

- **चीन वैश्विक ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार पर प्रभुत्व रखता है तथा विश्व के लगभग 85% ह्यूमनॉइड रोबोटों का उत्पादन करता है।**
- **इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स (IFR) के अनुसार, वर्ष 2024 में विश्वभर में स्थापित किए गए औद्योगिक रोबोटों में 54% हिस्सेदारी चीन की थी।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक चिप डिजाइन तथा उन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में अग्रणी है, जो भविष्य में ह्यूमनॉइड रोबोटों के "मस्तिष्क" के रूप में कार्य करेंगे।**

रोबोटिक्स में भारत की स्थिति

- **भारत ने वर्ष 2024 में 9,100 औद्योगिक रोबोट स्थापित किए, जो विगत वर्ष की तुलना में 7% अधिक है।**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- वार्षिक रोबोट स्थापना के आधार पर भारत विश्व में छठे स्थान पर है, जबकि उससे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया एवं जर्मनी हैं।
- भारत का रोबोट घनत्व लगभग 10 रोबोट प्रति 10,000 विनिर्माण श्रमिक है, जो वैश्विक औसत 132 रोबोट प्रति 10,000 श्रमिक से काफी कम है।
- SSI Mantra भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है, जिसने हजारों किलोमीटर की दूरी पर सफल टेली-सर्जरी का संचालन किया है।
- GreyOrange सहित अनेक भारतीय कंपनियाँ रोबोटिक्स विकास में सक्रिय हैं, किंतु चुनौती औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर रोबोट निर्माण की है।
- राष्ट्रीय रोबोटिक्स नीति (प्रारूप), 2023 के अनुसार, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक विनिर्माण, स्वास्थ्य, कृषि एवं राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों में रोबोटिक्स के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना है।

भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **कुशल मानव संसाधन की कमी**
- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता**
- **उच्च लागत:** स्थापना, एकीकरण, रखरखाव एवं सेवा प्रदान करने की लागत भी अधिक होती है।
- कम वहनीयता विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में रोबोटिक्स अपनाने को हतोत्साहित करती है।
- **तकनीकी सीमाएँ:** मूलभूत रोबोटिक्स प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान अभी प्रारंभिक अवस्था में है।
- उन्नत विनिर्माण, प्रोटोटाइप निर्माण एवं परीक्षण सुविधाओं का अभाव है।
- **सीमित नियामक व्यवस्था:** रोबोटिक्स के लिए व्यापक एवं समर्पित नियामक ढाँचे का अभाव है।
- गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, सुरक्षा मानकों तथा उत्तरदायित्व से संबंधित चिंताएँ बनी हुई हैं।
- **नैतिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ:** स्वचालन के कारण रोजगार में कमी आने की आशंका।

सरकारी पहलें

- **फ्यूचरस्किल्स प्राइम (FutureSkills Prime):** इस पहल के अंतर्गत उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दूरस्थ एवं स्व-गति अधिगम को बढ़ावा देने हेतु एक सुदृढ़ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है।
- **अटल नवाचार मिशन :** इस मिशन के अंतर्गत देशभर के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब (ATLs) स्थापित की जा रही हैं।
- इन प्रयोगशालाओं में रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर आधारित डू-इट-योरसेल्फ (DIY) किट उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके।
- **ई-यंत्र (e-YANTRA):** यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित तथा आईआईटी बॉम्बे द्वारा संचालित एक रोबोटिक्स प्रसार कार्यक्रम है।
- **मेक-इन-इंडिया रोबोट्स:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 'दक्ष' नामक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV) विकसित किया है, जो बहुउद्देशीय कार्यों के लिए एक स्वचालित मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म है।
- व्योममित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक मानवरूपी अंतरिक्ष रोबोट है, जिसे गगनयान मिशन में उपयोग हेतु विकसित किया गया है।
- मानव भारत का प्रथम 3D-प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसमें अंतर्निहित दृश्य एवं ध्वनि प्रसंस्करण क्षमता है, जिसके माध्यम से यह मानव निर्देशों के अनुसार चल, बोल और नृत्य कर सकता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली 'नेत्र' (Netra)

चर्चा में क्यों?

- भारतीय वायुसेना को स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) प्रणाली 'नेत्र' (Netra) के लिए अंतिम परिचालन स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

मुख्य बिन्दु:

- नेत्र प्रणाली को वर्ष 2015 में प्रारंभिक परिचालन स्वीकृति (IOC) प्रदान की गई थी तथा इसे वर्ष 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।
- इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) द्वारा किया गया है।
- यह ब्राज़ील निर्मित एम्ब्रेयर EMB-145I (145I) विमान मंच पर आधारित है।
- इसमें सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार लगा है, जिसकी 240–300 किलोमीटर तक की रडार क्षमता है।
- **महत्त्व:** भारत इस प्रकार की क्षमता विकसित करने वाला विश्व का पाँचवाँ देश बन गया है।
- नेत्र प्रणाली हवाई एवं समुद्री लक्ष्यों का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचान करने तथा निगरानी करने में सक्षम है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213